हमने दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की जो बैठक की थी उस बैठक में निर्णय ले लिया था कि प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द होनी चाहिए लेकिन इस सम्बन्ध में हम कानून नहीं बना सकते । इसलिए राज्य सरकारों के पास उचित कार्यवाही करने के लिए सिफारिश भेज दी गई है क्योंकि हमारे पास वह शक्ति नहीं है ।

श्री गजानन प्रधान : अध्यक्ष महोदय, देहातों में जाकर चिकित्सा कार्य डाक्टरों के लिए कम्पलसरी करने के लिए अभी तक केन्द्र ने कुछ नहीं किया है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार इस बारे में गाइडलाइन्स राज्यों को देने की कृपा करेगी ?

श्री राजनारायण : श्रीमन्, सम्मानित सदस्य का सुझाव अच्छा है । मैं समझता था कि एक न एक दिन इस तरह का प्रश्न सदन में उठेगा । (व्यवधान) सम्मानित सदस्य जरा सुन लें । हमारी इच्छा है मगर हमारी सभी इच्छायें कार्य रूप में परिणत हो जायें, यह आवश्यक नहीं है, हम तो चाहेंगे कि परिणत हो जायें । राज्य सरकारों के पास यह शक्ति है, हम उनसे कहते हैं कि हमने सेन्टर के लिए रोक लगा दी है, आप राज्यों के लिए भी रोक लगायें, आप भी इसका अनुकरण करें । एक बात मैं इस सम्मानित सदन की जानकारी के लिए बतला दूं कि हमने एक एक्सपर्ट कमेटी यहां पर बिठा रखी है डा० संकरन की अध्यक्षता में जोकि डायरेक्टर जनरल हैं । इसमें इंडियन मेडिकल कौंसिल के चेयरमैन हैं और इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज के डा० रामलिंगम् स्वामी हैं । ऐसे ऐसे एक्सपर्ट्स की यह कमेटी है । हम चाहते हैं कि यह कमेटी इन सारे पहलुओं पर विचार करे कि इन्टर्नशिप कितनी हो, हाउस जाब कब मिले, इन्टर्नशिप और हाउस जाब को क्या एक में मिला दिया जाये, पांच साल का कोर्स तीन साल कर दिया जाये या एक साल बढ़ा कर चार साल कर दिया जाये या प्रतिबंधित कर दिया जाये कि दो साल देहातों में काम करने के बाद तब सर्टिफिकेट दिया जाये ।

MR. SPEAKER: You have gone much beyond the question.

SHRI RAJ NARAIN: He wanted to know about this point.

SHRI VINODBHAI B. SHETH: In case Government propose to ban private practice by Government doctors, will the same formula apply to the teachers, including postgraduate teachers, in Ayurvedic Colleges where N. P. allowance is not given? There are many problems in respect of fixation of salary. If proper salary, in tune with the rising cost of living, is given, the doctors would not be lured to going in for private practice. I particularly draw your attention to the long-standing complaints of fixation of salaries, N. P. allowance, etc., of the teachers of the Ayurvedic University at Jamnagar, which is the first of its kind in the country ..

MR. SPEAKER: We are on a general question.

SHRI VINODBHAI B. SHETH: I want to know whether the same formula will be applicable to the teachers of Ayurvedic Colleges.

श्री राज नारायण : एक प्रकार से यह प्रश्न पहले ही आ चुका है । आपके द्वारा मैंने सदन से निवेदन किया था कि इन सारे मसलों पर विचार करने के लिए एक कमेटी हमने बनाई है और उस कमेटी की बैठक के लिए 29 तारीख भी तय हो गयी है । डा० संकरन जब मुझे जेनेवा में मिले थे तो मैंने उनसे पूछा था कि आप कमेटी की कब बुलायेंगे तो उन्होंने कहा कि 29 तारीख फिक्स करके आया हूं । तो उस कमेटी में यह सारी बातें तय होंगी । आप जानते हैं हमने सौ रुपया इन्टर्नीज का बढ़ा दिया और मैं उड़ीसा गया था तो उन्होंने कहा कि हम दो सौ देते थे आपने सौ क्यों बढ़ा दिया इस तरह से हमारी तो मुश्किल हो गई । (व्यवधान) इस तरह से एलोपैथी हो, यूनानी हो या होम्योपैथी हो, सभी के लिए विचार है ।

जिलों और सब-डिवीजनों और भागलपुर में स्वचालित टेलीफोन केन्द्रों का खोला जाना

*1073. डा० इलजी सिंह : क्या संचार मंत्री निम्नलिखित की जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) स्वचालित टेलीफोन केन्द्र स्थापित करने के मापदण्ड क्या हैं ;

(ख) जिला और सब-डिवीजन मुख्यालयों में कितने स्थानों पर स्वचालित टेलीफोन केन्द्र स्थापित किये गए हैं ;

(ग) क्या बिहार में भागलपुर में कोई स्वचालित टेलीफोन केन्द्र नहीं है जो केवल जिला ही नहीं बल्कि कमिश्नरी का मुख्यालय है और विश्वविद्यालय भी है और यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

(घ) वहां पर स्वचालित टेलीफोन केन्द्र कब तक स्थापित किया जायेगा ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) मौजूदा मैनुअल एक्सचेंज के स्थान पर आटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज लगाने के सम्बन्ध में सब से बड़ी कठिनाई यह रही है कि उपयुक्त आटोमेटिक टेलीफोन

स्विचिंग उपस्कर उपलब्ध नहीं हुए हैं। हर साल बहुत कम संख्या में मैनुअल एक्सचेंजों को आटोमेटिक एक्सचेंजों में बदलना संभव हुआ है। इस प्रयोजन के लिए मैनुअल एक्सचेंजों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में 500 से अधिक लाइनों के एक्सचेंज और दूसरी में 500 लाइनों और उससे कम लाइनों के एक्सचेंज रखे गए हैं। पहली श्रेणी के मैनुअल एक्सचेंजों को एम० ए० एक्स–I टाइप के उपस्करों में बदला जाता है और दूसरी श्रेणी के मैनुअल एक्सचेंजों के स्थान पर एम० ए० एक्स०–II टाइप के उपस्कर लगाये जाते हैं।

प्रत्येक श्रेणी में, आटोमेटिक एक्सचेंज लगाने की कार्रवाई करने के लिए निम्नलिखित मुख्य मानदंड अपनाए जाते हैं :—

(i) प्रत्येक स्थान पर टेलीफोनों की कुल मांग। जिन स्थानों पर टेलीफोन की मांग अधिक होती है उन स्थानों को प्राथमिकता दी जाती है।

(ii) क्या वह स्थान किसी राज्य या जिले का मुख्यालय है ? ऐसे प्रशासनिक मुख्यालयों को प्राथमिकता दी जाती है।

(iii) विशेष रूप से पहली श्रेणी के स्थानों पर आटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज की इमारत बनवाने के लिए उपयुक्त जमीन का उपलब्ध होना।

(ख) देश के 385 जिला मुख्यालयों में से 223 जिला मुख्यालयों में और 872 उप मंडल मुख्यालयों में से 415 उपमंडल मुख्यालयों में आटोमेटिक एक्सचेंज लगा दिए गए हैं।

(ग) भागलपुर में इस समय भी एक मैनुअल एक्सचेंज काम कर रहा है। वहां उपयुक्त जमीन उपलब्ध न होने के कारण आटोमेटिक एक्सचेंज स्थापित करने की योजना पहले नहीं बनाई जा सकी। 1977 में जमीन ले ली गई है और वहां आटोमेटिक एक्सचेंज लगाने की योजना बनाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

(घ) यदि कोई अप्रत्याशित परिस्थितियां उत्पन्न न हुईं तो आशा की जाती है कि भागलपुर में वर्ष 1983 तक आटोमेटिक एक्सचेंज चालू हो जाएगा।

डा० रामजी सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने तीन भाषखण्ड बतलाये हैं। जहां तक भागलपुर का प्रश्न है, वहां की मांग बहुत पुरानी है, वहां की आबादी 2 लाख से ज्यादा है, वह स्थान न केवल सब-डिवीजन का मुख्यालय है, बल्कि जिले का मुख्यालय है, कमिश्नरी का मुख्यालय है, विश्वविद्यालय का मुख्यालय है, बड़ी जैन तीर्थ चम्पा और विक्रम-शिला विश्वविद्यालय है। आप ने स्वयं स्वीकार किया है कि जमीन ले ली गई है, यदि ऐसा है तो फिर इस में क्या कठिनाई है कि इस को 1983 तक ले जाया जाय ?

श्री बृज लाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, जब तक जमीन उपलब्ध नहीं होती है, तब तक एक्सचेन्ज के लिये आर्डर प्लेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जमीन के अनुसार ही एक्सचेन्ज बना कर उस का आर्डर दिया जा सकता है। यहां पर जमीन प्राप्त करने में तीन-चार साल लग गये, अब वहां जमीन उपलब्ध हो गई है, जिस पर मकान बनाना शुरू कर दिया है और उसी हिसाब से एक्सचेन्ज को बनाने का आर्डर दिया है। वह एक्सचेन्ज 1980 तक आ जायेगा, उस के बाद उस को लगाना शुरू करेंगे और उम्मीद है 1983 तक चालू हो जायेगा।

डा० रामजी सिंह : हमारे संचार मंत्री जी के पास रिकार्ड होगा—समूचे हिन्दुस्तान में 4,642 आटोमेटिक एक्सचेंज हैं, जिन में आन्ध्र प्रदेश में 611, गुजरात में 337, केरल में 310, कर्णाटक में 394 और तमिलनाडु में 527 हैं। बिहार में जहां हिन्दुस्तान की आबादी का दसवां हिस्सा है, 229 आटोमेटिक एक्सचेन्ज हैं। क्या मैं आप से यह प्रार्थना कर सकता हूं कि बिहार के प्रति पिछले तीस वर्षों में जो अन्याय हुआ है, उस के रीजनल-इम्बैलेंस को खत्म करने की दिशा में प्रयत्न करेंगे और जहां भी टेलीफोन एक्सचेन्ज आटोमेटिक नहीं है, जिस में भागलपुर भी शामिल है, वहां जरा द्रुत-गति से काम करायेंगे ?

श्री बृजलाल वर्मा : इस पर निश्चित रूप से ध्यान दिया जायेगा और इस पर उचित ढंग से ख्याल किया जायेगा।

श्री सूरज बहादुर शाह : क्या मंत्री जी को यह ज्ञात है कि बहुत सी जगहों पर जहां नये आटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेन्ज बनाये जा रहे हैं, या बनाए गए हैं, वहां अन्य जगहों के डिस्कार्डेड एक्सचेन्ज लगा दिये जाते हैं ? इसका परिणाम यह होता है कि बड़ी पर जिस को एफिशिएन्ट-वर्किंग कहते हैं, वह नहीं हो पाती है। अगर उन को यह ज्ञात है तो क्या वे डिस्कार्डेड मशीनरी के स्थान पर उचित मशीनरी लगवाने की कृपा करेंगे।

श्री बृजलाल वर्मा : जैसी आप की शिकायत है, वैसी हमें शिकायत नहीं मिली है लेकिन अगर किसी जगह ऐसी बात हुई हो और उस के बारे में आप हमें निश्चित बतायें, तो उस जगह पर हम नई मशीनरी देंगे।

श्री हुकम देव नारायण यादव : सरकार ने जो जवाब दिया है, उस के बारे में अभी डा० रामजी सिंह ने सभी राज्यों के आंकड़े दिये कि वहां पर कितने स्वचालित टेलीफोन केन्द्र हैं और मंत्री जी ने कहा कि इस पर जरूर विचार करेंगे। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जब सरकार जमीन ले चुकी है और मकान बनाने की सोच रही है और सरकार यह सोचती है कि 1983 में इस को चालू करेंगे तो क्या सरकार अपने काम में तेजी ला कर 1983 से पहले ही भागलपुर में इस को चालू

कर देगी ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि भागलपुर की तरह बिहार में और भी दूसरे महत्वपूर्ण स्थान हैं जैसे गया है और दूसरी और ऐसी जगह हैं, तो उन जगहों के लिए इस तरह के टेलीफोन एक्सचेन्ज के मामले में बिहार की उपेक्षा क्यों हो रही है और इस के बारे में भी क्या मंत्री जी विचार करेंगे ?

श्री बृजलाल वर्मा: जी हां, उस पर विचार करेंगे। गया में भी मकान की कठिनाई है। इस कारण से अभी हम गया में नहीं खोल रहे हैं। गया में जमीन की उपलब्धि होते ही, वहां पर भी काम को शुरू कर देंगे।

मध्य प्रदेश में सार्वजनिक स्वास्थ्य कर्मचारी योजना के अन्तर्गत व्यक्तियों को प्रशिक्षण

*1074. श्री लक्ष्मीनारायण नायक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री निम्नलिखित की जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) मध्य प्रदेश में सार्वजनिक स्वास्थ्य कर्मचारी योजना के अन्तर्गत 31 मार्च, 1978 तक कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया;

(ख) प्रशिक्षण अवधि में सहायता के रूप में उन्हें कितनी धनराशि दी गई और क्या उक्त राशि सभी को दी गई है और यदि नहीं, तो ऐसे प्रशिक्षणार्थियों की जिलावार संख्या कितनी है जिन्हें अब तक उक्त धनराशि प्राप्त नहीं हुई है; और

(ग) टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है और क्या प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद इन सब व्यक्तियों को रोजगार मिल गया है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण): (क) 31 मार्च, 1978 तक प्रशिक्षित किये गये जन स्वास्थ्य रक्षकों की कुल संख्या 1671 है।

(ख) 31 दिसम्बर, 1977 तक 819 जन स्वास्थ्य रक्षकों के पहले बैच को प्रशिक्षित किया गया था तथा उन्हें जनवरी, 1978 में तीन महीनों के लिये 200/- रुपये प्रति मास की दर से अर्थात् प्रति व्यक्ति 600/- रुपये का वजीफा दिया गया था। दूसरे बैच अर्थात 852 जन स्वास्थ्य रक्षकों को, जिन्होंने 31 मार्च, 1978 तक अपना प्रशिक्षण पूरा किया, कितना वजीफ़ा दिया गया, यह सूचना जिला स्वास्थ्य अधिकारियों से अभी आनी शेष है। राज्य के जिला स्वास्थ्य अधिकारियों को स्वास्थ्य रक्षक के दूसरे बैच को वजीफा देने के लिए मंजूरी दे दी गयी है।

(ग) टीकमगढ़ जिले में 37 व्यक्ति और छतरपुर जिले में 24 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया। ये कार्यकर्ता सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। इन कार्यकर्ताओं ने प्रशिक्षण पाने के बाद अपने-अपने गांव में जन स्वास्थ्य रक्षक के रूप में कार्य करना आरम्भ कर दिया है।

श्री लक्ष्मीनारायण नायक : क्या माननीय मंत्री जी यह बताएंगे कि जिन जन स्वास्थ्य रक्षकों ने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है, क्या उन को सरकार ने उन की सहायता के लिए कुछ दवाइयां और दूसरे साधन दिये हैं, जिस से वे गांव में जा कर गांव वालों का इलाज अच्छी तरह से कर सकें ? सरकार इस मामले में उन की कोई सहायता करेगी ?

श्री राज नारायण : जी हां। जितने भी जन स्वास्थ्य रक्षक ट्रेनिंग ले कर निकलते हैं, उन को दवाइयों की पेटिका (किट) दी जाती है और उस में बराबर दवाइयां रहती हैं। इस के अलावा उन को 50 रुपए महीना बराबर दिया जाएगा, जब तक वे काम करते रहेंगे।

श्री लक्ष्मीनारायण नायक : दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि दूसरा बैच जो है, उस को वजीफा देने की स्वीकृति आप ने कब प्रदान की थी ?

श्री राज नारायण : स्वीकृति तो तभी से है जब से यह योजना चली। तभी से सब को मालूम है और केन्द्र की ओर से उनको बकायदा रकमें दे दी गई हैं। यह सही है कि किन्हीं-किन्हीं राज्यों में जो टैक्निकल बारीकियां होती हैं कि किस किस विभाग से रुपया आए और स्वास्थ्य मंत्रालय से आया नहीं है और फाइनेन्स मंत्रालय ने इस को ठीक किया है या नहीं, ऐसी बातें होती हैं। कुछ राज्यों में देने में विलम्ब हुआ है, मध्य प्रदेश में देने में विलम्ब हुआ है। अब इसके बारे में पता चल रहा है कि धीरे धीरे यह रुपया दिया जा रहा है।

श्री निर्मल चन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, सिवनी जिले में अभी तक कोई राशि नहीं बांटी गयी है। क्या स्वास्थ्य मंत्री जी बतायेंगे कि यह राशि बंट चुकी है या नहीं बंट चुकी है ? अगर अभी तक नहीं बंटी है तो यह कब तक बंट जाएगी।

श्री राज नारायण : हम इसकी जानकारी करायेंगे। जिस जिले का माननीय सदस्य ने जिक्र किया है उस जिले की जानकारी मेरे पास नहीं है कि वहां राशि बंट चुकी है या नहीं। मगर मैं इतना जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं कि वह रुपया जन स्वास्थ्य रक्षकों को मिलेगा और उसे कोई खा कर पचा नहीं सकेगा जब तक कि हम जिन्दा हैं।

श्री निर्मल चन्द्र जैन: कब तक मिलेगा ?

श्री राज नारायण : जल्दी से जल्दी और हर महीने मिलेगा।

SHRI B. K. NAIR: The Kerala Health Minister has given a statement in Newspapers to-day saying that the implementation of the scheme in Kerala